मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की बैठक में यूपी का एजेंडा प्रस्तुत किया, कहा-आपदा को अवसर में बदला

साझा प्रयासों से तेज विकास होगा: योगी

लखनऊ | प्रमुख संवाददाता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयासों से देश व प्रदेश को विकास की नई दिशा मिलेगी। गरीब, युवा, किसान, महिला व सभी वर्गों को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के मंत्र से भारत एक विश्व शक्ति के रूप में स्थापित हुआ है।

मुख्यमंत्री शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की छठी बैठक में अपने सरकारी आवास से वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में कोरोना ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में समय से लिए गए निर्णयों से देश आज सुरक्षित है। प्रधानमंत्री की प्रेरणा और मार्गदर्शन से राज्य सरकार ने इस आपदा को अवसर में बदलने का प्रयास किया। उन्होंने

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की बैठक में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।

प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यूपी 10 लाख लोगों को कोविड-19 वैक्सीन लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। प्रदेश द्वारा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के अंतर्गत 500 से अधिक रिफॉर्म लागू करते हुए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में देश में 12वें से दूसरे स्थान पर आ गया है।

उन्होंने कहा कि सकारात्मक नीतियों से कोरोना काल में अब तक 60 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इसके अलावा 6000 करोड़ रुपये की लागत के डेटा सेंटर पार्क, 4800 करोड़ रुपये लागत वाली देश की पहली डिस्प्ले निर्माण यूनिट व आईकिया द्वारा 5500 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। लैंड बैंक विकसित करते हुए ऑनलाइन माध्यम से 5,590 भूखंड आवंटित किए गए। इन्वेस्टर्स समिट में हस्ताक्षरित 4.68 लाख हजार करोड़ रुपये के सहमति पत्रों में करीब तीन लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं शुरू हो गई हैं। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 61 सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए।

मुख्यमंत्री ने यूपी में हो रहे नए काम गिनाए

- प्रदेश के 17 नगर निगमों को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा, केंद्र के पैसे से 10 और यूपी के पैसे से सात को बना रहे स्मार्ट सिटी
- ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर व वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बाधाओं को दूर कर दादरी को एक बड़े लॉजिस्टिक हब बनाएंगे
- दादरी, बोड़की व वाराणसी में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक ट्रान्सपोर्ट हब की स्थापना
- वाराणसी में देश का पहला फ्रेट विलेज लगभग 100 एकड़ में विकसित हो रहा
- प्रदेश के 825 विकास खंडों में एक-एक कृषि उत्पादक संगठन का गठन होगा
- 3,868 लाख टन गन्ने की पेराई कर 427.30 लाख टन चीनी का उत्पादन
- गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, झांसी व मेरठ में मेट्रो लाइट/मेट्रो नियो की स्थापना पर विचार

केंद्र-राज्यों में आपसी सहयोग पर जोर

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री ने राज्यों से रोजगार और निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ने की अपील की। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आजादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर देश के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए राज्य भी योगदान दें।

बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि राज्यों के साथ 6 फरवरी से ही गवर्निंग काउंसिल वाली बैठक के एजेंडा पर सहमति बनाने के लिए और राज्यों के मुद्दों को समझने के लिए चर्चा शुरू हो गई थी।

चर्चा में राज्यों और केंद्र सरकार के अधिकारियों, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के आधार पर ही 6 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया गया।